



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

No-158, 159, 160
see page-760

भाग II—खण्ड 3—खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 157]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 28, 1993/वैशाख 8, 1915

No. 157] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 28, 1993/VAISAKHA 8, 1915

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 1993

सं. का. नि. 388(अ):—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 642 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अन्तर्गत धारा 10ड की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कम्पनी विधि बोर्ड के सदस्य (अर्हताएं और अनुभव) नियम, 1989 की उन बातों के सिवाए जो ऐसे अधिकरणों से पूर्व की गई हैं या करने से रहे हैं, अधिकांश करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कम्पनी विधि बोर्ड (सदस्यों की अर्हताएं, अनुभव और सेवा शर्तें) नियम, 1993 है।

2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख की प्रभुता होंगे।

परिभाषा—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा न हो।

- (क) "अध्यक्ष" से कम्पनी विधि बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;
- (ख) "कम्पनी विधि बोर्ड" से कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 10ड की उपधारा (1) के अधीन पठित कम्पनी विधि प्रशासन बोर्ड अभिप्रेत है ;
- (ग) "कम्पनी विधि सेवा" से केन्द्रीय कम्पनी विधि सेवा नियम 1965 के नियम 3 के अधीन गठित केन्द्रीय कम्पनी विधि सेवा अभिप्रेत है ;
- (घ) "न्यायिक सदस्य" से कम्पनी विधि बोर्ड का न्यायिक सदस्य अभिप्रेत है ;
- (ङ) "सदस्य" से न्यायिक सदस्य या तकनीकी सदस्य अभिप्रेत है, और इसके अन्तर्गत उपाध्यक्ष और अध्यक्ष भी हैं ;
- (च) "तकनीकी सदस्य" से कम्पनी विधि बोर्ड का तकनीकी सदस्य अभिप्रेत है ;
- (छ) "उपाध्यक्ष" से कम्पनी विधि बोर्ड का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है।
3. सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं और आयु-सीमा
- (1) कोई व्यक्ति न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह—

(क) भारत के राजपत्र में कम से कम 10 वर्ष तक कोई न्यायिक पद धारण न कर चुका हो; या

(ख) किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता न रह चुका हो या कुल 10 वर्ष की अवधि तक कोई न्यायिक पद धारित न कर चुका हो और भागतः अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाई न रह चुका हो; या

(ग) कम्पनी विधि सेवा (विधिक शाखा) का सदस्य न हो या सदस्य न रह चुका हो और उस सेवा में अतिकाल श्रेणी या चयन श्रेणी में कोई पद या उस सेवा की श्रेणी 1 में कोई पद धारण किए हुए है या धारण किए हुए था; या

(घ) भारतीय विधि सेवा का सदस्य न हो या सदस्य न रह चुका हो और उस सेवा की श्रेणी II में कोई पद कम से कम तीन वर्ष तक या उस सेवा में कोई उच्चतर पद धारण किए हुए है या धारण किए हुए था ;

(2) कोई व्यक्ति तकनीकी सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह—

(क) कम्पनी विधि सेवा (लेखा शाखा) का सदस्य न हो या सदस्य न रह चुका हो और उस सेवा में अतिकाल श्रेणी या चयन श्रेणी में अथवा उस सेवा के श्रेणी 1 में कम से कम 8 वर्ष तक पद धारण किए हुए है या धारण किए हुए था; या

(ख) केन्द्रीय कर्मचारी बृन्द स्कीम के अधीन भारत सरकार के संयुक्त सचिव के रूप में या केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी ऐसे पद पर नियुक्त किए जाने के लिए पात्र न हो जिसके वेतनमान भारत सरकार के संयुक्त सचिव के वेतनमान से कम न हो और कम्पनी विधि से संबंधित समस्याओं के निपटान के संबंध में पर्याप्त ज्ञान और अनुभव रखता हो; या

(ग) कम से कम 15 वर्ष तक चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अधीन चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट के रूप में व्यवसायी न हो या न रह चुका हो; या

(घ) कम से कम 15 वर्ष तक लागत और संकर्म अकाउन्टेन्ट अधिनियम, 1959 (1959 का 33) के अधीन लागत लेखाकार के रूप में व्यवसायी न हो या न रह चुका हो; या

(ङ) कम से कम 15 वर्ष तक कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 2 के खण्ड (45क) में यथा परिभाषित पूर्णकालिक व्यवसाय करने वाले सचिव के रूप में कार्य करने का अनुभव न रखता हो और कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) के अधीन गठित भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान का सदस्य है ।

(3) कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि उसने पैतालिस वर्ष की आयु पूरी न कर ली हो।

(4) कोई व्यक्ति उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि उसने सदस्य के रूप में दो वर्ष से अन्यून अवधि तक पद धारण न किया हो।

(5) कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि—

(क) वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो या न रहा हो, अथवा होने के लिए अर्हित न हो; या

(ख) उसने उपाध्यक्ष के रूप में तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक पद धारण न किया हो।

4. भर्ती की पद्धति :—(1) सदस्यों का चयन भारत सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाध्वी या उसके निर्देशों के परामर्श से किया जाएगा।

(2) इस नियम की कोई बात, कम्पनी विधि बोर्ड, के अध्यक्ष या किसी सदस्य को, जो इन नियमों के प्रारम्भ के ठीक पूर्व उस रूप में कृत्य कर रहा है, नियुक्ति को लागू नहीं होगी।

5. बिकल्पक दृष्टया योग्यता :—कोई भी व्यक्ति सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित किए जाने वाले बिकल्प बोर्ड द्वारा बिकल्पक दृष्टया योग्य घोषित नहीं कर दिया जाता है, यदि उसे किसी समुचित प्राधिकारों द्वारा पहले ही योग्य घोषित न कर दिया हो।

6. किसी सदस्य द्वारा पद त्याग :—कोई सदस्य केन्द्रीय सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा किसी भी समय अपना पद त्याग सकेगा—

परन्तु सदस्य, जब तक कि उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा पहले ही पद छोड़ने के अनुमत नहीं कर दिया गया हो, ऐसे सूचना का प्रेषण की तारीख से तीन मास समाप्त होने तक या पदों अवधि के रूप में सत्यक रूप से नियुक्त व्यक्ति के अपने पद ग्रहण करने तक या अपने पद की अवधि समाप्त होने तक, जो भी पूर्वतम हो, पद धारण करता रहेगा।

7. कुछ परिस्थितियों में सदस्यों का पद से हटाया जाना :—केन्द्रीय सरकार भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किसी ऐसे सदस्य को पद से हटा सकेगी—

(क) जिसे दिवालिया न्यायनिर्णय किया गया है; या

(ख) जिसे किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धोप ठहराया गया है जिसमें, केन्द्रीय सरकार का राय में, नैतिक अधभता अंतर्वलित है; या

(ग) जो ऐसे सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक या मानसिक रूप से अधभ हो गया है; या

(घ) जिसने ऐसा वित्तिय या अन्यहित अर्जित किया है जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का संभावना है; या

(ङ) जिसने अपने पद का ऐसा दुरुपयोग किया है कि उसके पद पर बने रहने से लोक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

परन्तु इस नियम की कोई बात किसी ऐसे अध्यक्ष को लागू नहीं होगी जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है।

परन्तु यह और कि जहां किसी सदस्य को खंड (ख) से खंड (ङ) तक में विनिर्दिष्ट आधारों में से किसी आधार पर हटाए जाने की प्रस्तावना है वहां उस सदस्य को उसके विरुद्ध आरोपों के बारे में सूचित किया जाएगा और उन आरोपों के बाबत सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा।

8. अध्यक्ष और सदस्यों के पद की अवधि :—नियम 6 या नियम 7 में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष तब तक पद धारण करेगा जब तक कि वह बासठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता और कोई अन्य सदस्य तब तक पद धारण करेगा जब तक कि वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता।

9. वेतन और भत्ते :—(1) अध्यक्ष को प्रति मास 8, (नियत) वेतन का संदाय किया जाएगा—

(2) उपाध्यक्ष को 7300-160-7600 रु. के वेतनमान में वेतन का सदाय किया जाएगा।

(3) सदस्य को 8800-200-6700 रु. वेतनमान में वेतन का सदाय किया जाएगा।

(4) अध्यक्ष और सदस्य वे मते लेने के हकदार होंगे जो केन्द्रिय सरकार के वह वेतन या वेतनमान वाला सगृह के पद धारण कर रहे अधिकारी को अनुज्ञेय हैं।

10. निम्नलिखित--यदि इन नियमों के निर्वाचन के तबध में कोई प्रश्न उत्पन्न है तो उसे केन्द्रिय सरकार को उसके विनियम के लिए निदिष्ट किया जाएगा।

11. व्यापृति--इन नियमों का कोई बात केन्द्रिय सरकार द्वारा संघर्ष में समन्वयन पर धारा किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और व्यक्तियों के अन्य विशेष प्रवर्तों के लिए उपाधिया किए जाने के लिए ओशिता आरक्षण आधु संसा में छूट और अन्य रिशायतों पर प्रभाव नहीं डालेगा।

12. पद और गोपनीयता का शपथ--अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, जसना पद ग्रहण करने से पूर्व, इन नियमों से उपावद्ध प्ररूप 1 और प्ररूप 2 में पद और गोपनीयता का शपथ लेगा और उन पर हस्ताक्षर करेगा।

13. सेवा का अन्त्य पाठ :-ऐसे विषयों की बावत किसे सदस्य की सेवा का शर्त, इसके लिए इन नियमों में कोई उपबंध नहीं किया गया है जैसी हा होंगे जैसी कि उस समय भारत सरकार के तत्तमान हैसियत के अन्य कर्तव्यारियों को लागू है।

प्ररूप 1

(नियम 12 देखिए)

कम्पनी विधि बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य के लिए पद की शपथ का प्ररूप।

"मैं, अनुक्त, जिसे कम्पनी विधि बोर्ड का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य नियुक्त किया गया है, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, कि मैं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और श्रद्धा आकरण से जसना सर्वोच्च योग्यता, जातकार और विवेकबुद्धि के अनुसार, मन जापजपात, अनुराग या वैमनस्य के बिना, निर्वहन करूंगा।"

प्ररूप 2

(नियम 12 देखिए)

कम्पनी विधि बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य के लिए गोपनीयता का शपथ का प्ररूप।

"मैं, अनुक्त, जिसे कम्पनी विधि बोर्ड का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य नियुक्त किया गया है, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं कोई ऐसा विषय, जिसे कम्पनी विधि बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य के रूप में मेरे विवेकाध्य लाया जाएगा या भी मुझे ज्ञात होगा, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के, सब के सिवाय जबकि ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्पन्न निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्णित या प्रकट नहीं करूंगा।"

[फाइल सं. ए--12018/3, 92-एजी-1]

को. वेंकटरमणन्, अपर सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April, 1993

GSR 388(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 10E, read with clause (a) of sub-section (1) of section 642, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), and in supersession of the Company Law Board Members (Qualifications and Experience) Rules, 1989, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the follownig rules, namely,—

1. Short title and commencement :—(1) These rules may be called the Company Law Board (Qualifications, Experience and other Conditions of Service of Members) Rules, 1993.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions :—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Chairman" means Chairman of the Company Law Board;

(b) "Company Law Board" means the Board of Company Law Administration constituted under sub-section (1) of section 10E of the Companies Act, 1956 (1 of 1956);

(c) "Company Law Service" means the Central Company Law Service constituted under rule 3 of the Central Company Law Service Rules, 1965;

(d) "Judicial Member" means a Judicial Member of the Company Law Board;

(e) "Member" means a Judicial Member or Technical Member and includes the Vice-Chairman and the Chairman;

(f) "Technical Member" means a Technical Member of the Company Law Board;

(g) "Vice-Chairman" means Vice-Chairman of the Company Law Board.

3. Qualifications and age limit for appointment of Members :—(1) A person shall not be qualified for appointment as Judicial Member unless he—

(a) has, for at least ten years, held a judicial office in the territory of India; or

(b) has, for at least ten years, been an Advocate of High Court, or has partly held judicial office and has been partly in practice as an Advocate for a total period of ten years; or

(c) is, or has been, a Member of the Company Law Service (Legal Branch) and is holding, or has held, a post in Super-Time Grade or Selection Grade in that Service or a post in Grade I of that Service for at least eight years; or

(d) is, or has been a Member of the Indian Legal Service and is holding, or has held a post in Grade II of that Service for at least three years, or any higher post in that Service;

(2) A person shall not be qualified for appointment as Technical Member unless he—

(a) is, or has been, a Member of the Company Law Service (Accounts Branch) and is holding, or has held, a post in Super-Time Grade or Selection Grade in that service or a post in Grade I of that Service for at least eight years; or

(b) is eligible to be appointed as a Joint Secretary to the Government of India under the Central Staffing Scheme, or to any other post under the Central Government carrying a scale of pay which is not less than that of Joint Secretary to the Government of India, and has adequate knowledge of and experience in dealing with the problems relating to Company Law; or

(c) is, or has been, for at least fifteen years in practice as a Chartered Accountant under the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949); or

(d) is, or has been, for at least fifteen years in practice as a Cost Accountant under the Costs and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959); or

(e) has, for at least fifteen years, working experience as a Secretary in whole time practice as defined in clause (45A) of section 2 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and is a member of the Institute of Company secretaries of India constituted under the Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980).

(3) A person shall not be eligible for appointment as Member unless he has completed the age of forty five years.

(4) A person shall not be eligible for appointment as Vice-Chairman unless he has for a period of not less than two years held office as Member.

(5) A person shall not be eligible for appointment as Chairman unless he—

(a) is, or has been, or is qualified to be, a Judge of a High Court; or

(b) has for a period of not less than three years held office as Vice-Chairman.

4. Method of recruitment :—(1) The selection of Members shall be made by the Government of India in consultation with the Chief Justice of India or his nominee.

(2) Nothing in this rule shall apply to the appointment of Chairman or any Member of the Company Law Board functioning as such immediately before the commencement of these rules.

5. Medical Fitness.—No person shall be appointed as a Member unless he is declared medically fit by a Medical Board to be constituted by the Central Government for the purpose, unless he has already been declared fit by an equivalent authority.

6. Resignation by a Member :—A Member may, by writing under his hand addressed to the Central Government, resign his office at any time.

Provided that the Member shall, unless he is permitted by the Central Government to relinquish office sooner, continue to hold office until the expiry of three months from the date of receipt of such notice or until a person duly appointed as a successor enters upon his office or until the expiry of his term of office, whichever is earliest.

7. Removal of members from office in certain circumstances :—The Central Government in consultation with Chief Justice of India, may remove from office any Member, who—

(a) has been adjudged an insolvent; or

(b) has been convicted of an offence which, in the opinion of the Central Government, involves moral turpitude; or

(c) has become physically or mentally incapable of acting as such member; or

(d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as a member; or

(e) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest.

Provided that nothing contained in this rule shall apply to a Chairman who is a Judge of a High Court.

Provided, further, that where a Member is proposed to be removed on any of the grounds specified in clauses (b) to (e), the Member shall be informed of the charges against him and given a reasonable opportunity of being heard in respect of those charges.

8. Term of office of Chairman and Members :—Except as provided in rule 6 or rule 7, the Chairman or Vice-Chairman shall hold office till he attains the age of sixty two years and any other Member shall hold office till he attains the age of sixty years.

9. Salary and allowances :—(1) The Chairman shall be paid a salary of Rs. 8,000 per month (fixed);

(2) The Vice-Chairman shall be paid a salary in the scale of pay of Rs. 7300-100-7600;

(3) A Member shall be paid a salary in the scale of Rs. 5900-200-6700.

(4) The Chairman and Members shall be entitled to draw allowances as are admissible to a Central Government officer holding Group 'A' post carrying the same pay or scale of pay.

10. Interpretation :—If any question arises relating to the interpretation of these rules, the same shall be referred to the Central Government for its decision.

11. Saving :—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

12. Oaths of office and secrecy :—Every person appointed to be Chairman or a Vice-Chairman or a Member shall, before entering upon his office, make and subscribe an oath of office and secrecy in Forms I and II annexed to these rules.

13. Other conditions of Services :—The conditions of service of a Member in respect of matters for which no provision is made in these rules shall be the same as may for the time being be applicable to other employees of the Government of India of a corresponding status.

FORM I

(See rule 12)

Form of oath of office for Chairman/Vice-Chairman/
Member of the Company Law Board.

"I, A.B., having been appointed as Chairman/Vice-Chairman/Member of the Company Law Board do solemnly affirm/do swear in the name of God that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Chairman/Vice Chairman/Member to the best of my ability, knowledge and judgement, without fear or favour affection or ill-will."

FORM II

(See rule 12)

Form of oath of secretary for Chairman/Vice-Chairman/Member of the Company Law Board.

"I, A.B., having been appointed as Chairman/Vice-Chairman/Member of the Company Law Board, do solemnly affirm/do swear in the name of God, that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Chairman/Vice-Chairman/Member of the said Company Law Board except as may be required for the due discharge of my duties as the Chairman/Vice-Chairman/Member."

[File No. A-12018/3/92-Ad.I]

G. VENKATARAMAN. Addl. Secy.

